



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-03052025-262865
CG-DL-W-03052025-262865

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 3—मई 9, 2025 (वैशाख 12, 1947)
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 3—MAY 9, 2025 (VAISAKHA 12, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	261	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	381	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2457	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	1469
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1973
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	261	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	381	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2457	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1469
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1973
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 मई 2025

सं. 4/1/2025/पीएसी—लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को 01 मई, 2025 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2026 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया गया है:—

लोक सभा

1. श्री टी.आर. बालू
2. डॉ. निशिकान्त दुबे
3. श्री जगदम्बिका पाल
4. श्री जय प्रकाश
5. श्री रवि शंकर प्रसाद
6. डॉ. सी.एम. रमेश
7. प्रो. सौगत राय
8. श्री मंगुटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
9. श्रीमती अपराजिता सारंगी
10. डॉ. अमर सिंह
11. श्री तेजस्वी सूर्या
12. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
13. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
14. श्री के.सी. वेणुगोपाल
15. श्री धर्मेन्द्र यादव

राज्य सभा

16. श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण
17. श्री शक्तिसिंह गोहिल
18. डॉ. के. लक्ष्मण
19. श्री प्रफुल्ल पटेल
20. श्री सुखेंद्रु शेखर राँय

21. श्री तिरुची शिवा
22. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
2. अध्यक्ष ने श्री के. सी. वेणुगोपाल को समिति का सभापति नियुक्त किया है।

मुरलीधरन. पी
निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 मई 2025

सं. 4/1-पीयू/2025—लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2025-2026), जिसका कार्यकाल 1 मई, 2025 को आरंभ होगा और 30 अप्रैल, 2026 को समाप्त होगा, के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु चुना गया है :—

लोकसभा

1. श्री तारिक अनवर
2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
4. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्री शंकर लालवानी
7. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
8. श्री वैजयंत पांडा
9. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र
10. श्री मुकेश राजपूत
11. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा
12. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
13. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
14. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी
15. श्री लालजी वर्मा

राज्यसभा

16. डॉ. जॉन ब्रिटान
17. श्री नीरज डांगी
18. श्री मिलिंद मुरली देवड़ा
19. डा. भागवत कराड
20. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
21. श्री देवाशीष सामंतराय
22. श्री अरूण सिंह

लोक सभा अध्यक्ष ने श्री वैजयंत पांडा, संसद सदस्य को समिति (2025-2026) के सभापति के रूप में नियुक्त किया है।

अंजनी कुमार
संयुक्त सचिव

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 अप्रैल 2025

सं. एआई-17011/1/2023-एआईपीएसयू-डीबीटी [एफटीएस-18871]—मोहाली, पंजाब में स्थित स्वायत्तशासी संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैवप्रौद्योगिकी संस्थान (एनएबीआई) और नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैवप्रसंस्करण केंद्र (सीआईएबी) भविष्य में एक निदेशक (अर्थात् कार्यकारी निदेशक, एनएबीआई के नेतृत्व में) की सहायता से एक ही स्वायत्तशासी संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय कृषि-खाद्य तथा जैवनिर्माण संस्थान (बीआरआईसी-एनएबीआई) के रूप में कार्य करेगा। इस नए स्वायत्तशासी संस्थान का नया चिन्ह निम्नानुसार होगा।



एकता विश्नोई
संयुक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2025

सं. 9-3/2017-यू 3(ए)—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर उच्चतर शिक्षा के किसी संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर दिनांक 29.11.2019 की अधिसूचना संख्या 9-3/2017-यू.3(ए) के तहत चैतन्य डिग्री कॉलेज (स्वायत्त), हनमकोंडा, वारंगल, तेलंगाना को संभावित तिथि के साथ पांच वर्ष की अंतरिम अवधि के लिए सामान्य श्रेणी के अंतर्गत चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल, तेलंगाना के नाम पर एक सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया है।

3. और जबकि, इस मंत्रालय ने दिनांक 29.11.2019 की अधिसूचना संख्या 9-3/2017-यू3(ए) के तहत चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय), हनमकोंडा, वारंगल का नाम बदलकर चैतन्य (सम विश्वविद्यालय), हनमकोंडा, वारंगल कर दिया।

4. और जबकि, इस मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर दिनांक 21.07.2023 की अधिसूचना संख्या 9-3/2017-यू.3(ए) के तहत चैतन्य (सम विश्वविद्यालय), हनमकोंडा, वारंगल को अपने मुख्य परिसर को हनमकोंडा, वारंगल से हैदराबाद के आस-पास स्थानांतरित करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी थी कि चैतन्य (सम विश्वविद्यालय) का हनमकोंडा, वारंगल परिसर इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा।

5. और आगे, जबकि चैतन्य (सम विश्वविद्यालय), हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा अपने सम विश्वविद्यालय के दर्जे को दिनांक 28.11.2024 से आगे बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यूजीसी से अनुरोध किया गया था कि वह प्रस्ताव की जांच करें और इस मंत्रालय को अपनी सलाह प्रस्तुत करें।

6. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 24.03.2025 के अपने पत्र संख्या 1-5/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार यूजीसी विशेषज्ञ समिति की मदद से आवेदन की जांच की गई। विशेषज्ञ समिति ने सम विश्वविद्यालय का दर्जा बढ़ाने की सिफारिश की। आयोग ने 13.03.2025 को आयोजित अपनी 588वीं बैठक (मद संख्या 2.07) में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

7. अब, इसलिए, यूजीसी की सलाह पर, केंद्र सरकार, एतद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चैतन्य, हैदराबाद, तेलंगाना का सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिनांक 28.11.2024 से आगे बढ़ाती है।

8. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों का चैतन्य (सम विश्वविद्यालय), हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा पालन किया जाना जारी रहेगा।

पूर्णन्दु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

सं. 9-5/2024-यू.3(ए)—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर, उच्चतर शिक्षा संस्थान को समविश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सोसायटी (एफटीआईआई सोसायटी), पुणे द्वारा यूजीसी के सम विश्वविद्यालय आवेदन पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया गया था।

3. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 07.08.2024 के अपने पत्र संख्या 30-4/2024 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी विशेषज्ञ समिति ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार आवेदन की जांच करने के बाद सिफारिश की कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को एक सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए एफटीआईआई सोसायटी को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जा सकता है। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 24.07.2024 को आयोजित अपनी 582वीं बैठक (मद संख्या 2.07) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

4. और जबकि, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को एक समविश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए एफटीआईआई सोसायटी को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

5. और आगे जबकि, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के निदेशक ने दिनांक 17.01.2025 के अपने पत्र के माध्यम से एलओआई की शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सत्यापन और उसकी सलाह के लिए यूजीसी को भेजा गया। यूजीसी ने अनुपालन रिपोर्ट उसी विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखी जिसने आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी। विशेषज्ञ समिति ने संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट स्वीकार की। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 13.03.2025 को आयोजित अपनी 588वीं बैठक (मद संख्या 7.02) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एतद्वारा यूजीसी की सलाह पर, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को एक विशिष्ट श्रेणी के तहत एक समविश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है:

- i. यूजीसी और केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, समविश्वविद्यालय संस्थान/या इसके घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- ii. एफटीआईआई, पुणे किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- iii. एफटीआईआई, पुणे में संचालित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- iv. एफटीआईआई, पुणे नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम, ऑफ-कैंपस, ऑफ-शोर कैंपस केवल यूजीसी द्वारा समय-समय पर इस विषय पर जारी मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार शुरू करेगा।
- v. एफटीआईआई, पुणे अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ-साथ डॉक्टरेट और नवीन शैक्षणिक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उचित कदम उठाएगा। संस्थान केवल वर्तमान में नए उभरते क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह यूजीसी विनियमों/दिशानिर्देशों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने का प्रयास करेगा।
- vi. एफटीआईआई, पुणे सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध प्रत्यायन के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
- vii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन का नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और एफटीआईआई, पुणे द्वारा उनका पालन किया जाएगा।
- viii. एफटीआईआई, पुणे यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार अपना संशोधित संगम ज्ञापन (एमओए)/नियम यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय को जल्द से जल्द प्रस्तुत करेगा। जब भी आवश्यक होगा, संस्थान प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।
- ix. एफटीआईआई, पुणे यूजीसी और प्रासंगिक सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।

- x. एफटीआईआई, पुणे इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xi. एफटीआईआई, पुणे को अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाना होगा, अपने विद्यार्थियों की पहचान करनी होगी तथा उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में दिखाई दें तथा समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाना होगा।

पूर्णन्दु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

सं. 9-6/2024-यू.3(ए)—जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई), ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास, पंचसायर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संख्या का दर्जा देने के लिए सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट सोसाइटी (एसआरएफटीआई सोसाइटी) द्वारा यूजीसी के पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

2. और जबकि, यूजीसी ने अपने दिनांक 07.08.2024, के पत्र सं. 45-1/2024 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई), कोलकाता, पश्चिम बंगाल को एक सम विश्वविद्यालय संस्था घोषित करने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए एसआरएफटीआई सोसाइटी को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी।

3. और इसके अलावा जबकि, शिक्षा मंत्रालय ने, यूजीसी की सलाह पर, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई), कोलकाता, पश्चिम बंगाल को एक सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए एसआरएफटीआई सोसाइटी को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया था।

4. और जबकि, एसआरएफटीआई सोसाइटी ने दिनांक 10.01.2025 के पत्र के माध्यम से आशय पत्र (एलओआई) की शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अनुपालन रिपोर्ट की यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की गई और स्वीकार किया गया। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 25.03.2025 को आयोजित अपनी 588वीं बैठक (मद संख्या 7.03) में विचार किया गया और उसे अनुमोदित किया गया।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एतद द्वारा यूजीसी की सलाह पर, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास, पंचसायर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को एक विशिष्ट श्रेणी के तहत एक सम विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है:

- i. यूजीसी और केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, सम विश्वविद्यालय संस्था/या उसके संघटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- ii. एसआरएफटीआई, कोलकाता किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ अर्जन प्रकृति की हो।
- iii. एसआरएफटीआई, कोलकाता में संचालित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित वैधानिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- iv. एसआरएफटीआई, कोलकाता इस विषय पर यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार ही नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम, ऑफ-कैंपस, ऑफ-शोर कैंपस शुरू करेगा।
- v. एसआरएफटीआई, कोलकाता अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ-साथ डॉक्टरेट और नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए उचित कदम उठाएगा। यह संस्थान केवल वर्तमान में नए उभरते क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह यूजीसी विनियमों/दिशानिर्देशों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने का प्रयास करेगा।
- vi. एसआरएफटीआई, कोलकाता समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार, सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
- vii. विद्यार्थियों के प्रवेश, विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित वैधानिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी, और एसआरएफटीआई, कोलकाता द्वारा उनका पालन किया जाएगा।
- viii. एसआरएफटीआई, कोलकाता यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार यथाशीघ्र यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय को अपना संशोधित संगम ज्ञापन (एमओए)/नियमावली प्रस्तुत करेगा। संस्थान जब भी आवश्यक हो, मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमावली को अद्यतित या संशोधित या परिवर्तित करेगा।

- ix. एसआरएफटीआई, कोलकाता यूजीसी और प्रासंगिक सांविधिक परिषदों की नियमावली और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- x. एसआरएफटीआई, कोलकाता इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xi. एसआरएफटीआई, कोलकाता अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) का सृजन करेगा, अपने छात्रों की पहचान करेगा और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में प्रतिबिंबित हो और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएगा।

पूर्णन्दु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st May 2025

No. 4/1/2025/PAC—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve as Members of the Committee on Public Accounts for the term beginning on 01 May, 2025 and ending on 30 April, 2026:—

LOK SABHA

1. Shri T. R. Baalu
2. Dr. Nishikant Dubey
3. Shri Jagdambika Pal
4. Shri Jai Parkash
5. Shri Ravi Shankar Prasad
6. Dr. C. M. Ramesh
7. Prof. Sougata Ray
8. Shri Magunta Sreenivasulu Reddy
9. Smt. Aparajita Sarangi
10. Dr. Amar Singh
11. Shri Tejasvi Surya
12. Shri Anurag Singh Thakur
13. Shri Balashowry Vallabhaneni
14. Shri K. C. Venugopal
15. Shri Dharmendra Yadav

RAJYA SABHA

16. Shri Ashokrao Shankarrao Chavan
17. Shri Shaktisinh Gohil
18. Dr. K. Laxman
19. Shri Praful Patel
20. Shri Sukhendu Sekhar Ray
21. Shri Tiruchi Siva
22. Dr. Sudhanshu Trivedi

2. The Speaker has been pleased to appoint Shri K C Venugopal as the Chairperson of the Committee.

MURALEEDHARAN. P
Director

New Delhi-110001, the 1st May 2025

No. 4/1-PU/2025—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve on the Committee on Public Undertakings w.e.f. 1st May, 2025 for the term 2025-26 ending on 30th April, 2026:—

LOK SABHA

1. Shri Tariq Anwar
2. Shri Sudip Bandyopadhyay
3. Shri Chandra Prakash Joshi
4. Smt. Kanimozhi Karunanidhi
5. Shri Kaushalendra Kumar

6. Shri Shankar Lalwani
7. Smt. Poonamben Hematbhai Maadam
8. Shri Bajjayant Panda
9. Shri B.Y. Raghavendra
10. Shri Mukesh Rajput
11. Shri Sukhjinder Singh Randhawa
12. Shri Pratap Chandra Sarangi
13. Shri Kodikunnal Suresh
14. Shri Prabhakar Reddy Vemireddy
15. Shri Lalji Verma

RAJYA SABHA

16. Dr. John Brittas
17. Shri Neeraj Dangi
18. Shri Milind Murli Deora
19. Dr. Bhagwat Karad
20. Shri Surendra Singh Nagar
21. Shri Debashish Samantaray
22. Shri Arun Singh

The Speaker, Lok Sabha has appointed Shri Bajjayant Panda, MP as Chairperson of the Committee (2025-26).

ANJANI KUMAR
Joint Secretary

**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)**

New Delhi-110030, the 28th April 2025

No. AI-17011/1/2023-AIPSU-DBT [FTS-18871]—The Autonomous Institutes namely National Agri-Food Biotechnology Institute (NABI), and Center for Innovative and Applied Bioprocessing (CIAB) located at Mohali, Punjab will function as one Autonomous Institute namely National Agri-Food And Biomanufacturing Institute (BRIC-NABI) with one Director (i.e. headed by Executive Director, NABI). The new logo of the new AI would be as under:



EKTA VISHNOI
Joint Secretary

**MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)**

New Delhi, the 22nd April 2025

No. 9-3/2017-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, this Ministry, vide Notification No.9-3/2017-U.3(A) dated 29.11.2019, on the advice of UGC, declared Chaitanya Degree College (Autonomous), Hanamkonda, Warangal, Telangana as an Institution deemed to be University in the name of Chaitanya Institute of Science & Technology, Warangal, Telangana under general category for a provisional period of five years with prospective date.

3. And whereas, this Ministry, vide Notification No.9-3/2017-U.3(A) dated 29.11.2019, rechristened the name of Chaitanya Institute of Science & Technology (Deemed to be University), Hanamkonda, Warangal to Chaitanya (Deemed to be University), Hanamkonda, Warangal.

4. And whereas, this Ministry, vide Notification No.9-3/2017-U.3(A) dated 21.07.2023, on the advice of UGC, permitted Chaitanya (Deemed to be University), Hanamkonda, Warangal for shifting of its main campus from Hanamkonda, Warangal to the vicinity of Hyderabad with condition that the Hanamkonda, Warangal campus of Chaitanya (Deemed to be University) will cease to exist after one year from the date of issuance of this Notification.

5. And further whereas, a proposal was submitted by Chaitanya (Deemed to be University), Hyderabad, Telangana for extension of its deemed to be University status beyond 28.11.2024. UGC was requested to examine the proposal and submit its advice to this Ministry.

6. And whereas, UGC, vide its letter no. 1-5/2023 (CPP-I/DU) dated 24.03.2025 informed that the application was examined with the help of an UGC Expert committee in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. The Expert Committee recommended for extension of the deemed to be University status. The Commission considered and approved the recommendation of UGC Expert Committee in its 588th meeting (Item No. 2.07) held on 13.03.2025.

7. Now, therefore, on the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of Chaitanya, Hyderabad, Telangana beyond 28.11.2024.

8. All the other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the rules / regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered to by Chaitanya (Deemed to be University), Hyderabad, Telangana.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary

No. 9-5/2024-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, an online application was uploaded on UGC's Deemed Universities Application Portal by Film and Television Institute of India Society (FTII Society), Pune for grant of Institution Deemed to be University status under Distinct Category to Film and Television Institute of India (FTII), Pune under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. And whereas, UGC, vide its letter No. 30-4/2024 (CPP-I/DU) dated 07.08.2024, informed that UGC Expert Committee, after examining the application as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023, recommended that Letter of Intent (LoI) may be issued to FTII Society for fulfilment of certain conditions before declaration of Film and Television Institute of India, Pune as an Institution deemed to be University. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 582nd meeting (Item No. 2.07) held on 24.07.2024.

4. And whereas, the Ministry of Education, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LOI) to FTII Society for fulfilment of the certain conditions within a period of three years before declaration of Film and Television Institute of India, Pune as an Institution deemed to be University.

5. And further whereas, Director, Film and Television Institute of India, Pune, vide his letter dated 17.01.2025, submitted compliance report of the conditions of the LoI which was then sent to UGC for verification and its advice. UGC placed the compliance report before the same Expert Committee which had recommended for issuance of Letter of Intent (LoI). The Expert Committee accepted the compliance report of the Institution. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 588th meeting (Item No.7.02) held on 13.03.2025.

6. Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares Film and Television Institute of India, Pune as an Institution deemed to be University under distinct category. The said declaration is subject to the following conditions:

- i. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Central Government.
- ii. FTII, Pune shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- iii. The academic programmes to be offered at FTII, Pune shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.

- iv. FTII, Pune shall start new academic Courses/Programmes, Off-Campus(es), Off-Shore Campus(es) only in accordance with the norms and guidelines issued by the UGC, from time to time, on the subject.
- v. FTII, Pune shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes. The Institute shall not keep confined only to presently new emerging areas but it make endeavour to expand in other areas in accordance with the UGC Regulations / Guidelines as well as National Education Policy-2020.
- vi. FTII, Pune shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- vii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by FTII, Pune.
- viii. FTII, Pune shall submit its revised Memorandum of Association (MoA) / Rules to UGC/ Ministry of Education as per the provisions of the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 at the earliest. As and when necessary, the Institute shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- ix. FTII, Pune shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- x. FTII, Pune shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xi. FTII, Pune shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary

No. 9-6/2024-U.3(A)—Whereas, an online application was submitted by Satyajit Ray Film and Television Institute Society (SRFTI Society) on the UGC's Portal for grant of Institution Deemed to be University status under Distinct Category to Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), Eastern Metropolitan Bypass, Panchasayar, Kolkata, West Bengal under Section 3 of the UGC Act, 1956.

2. And whereas, UGC, vide its letter no. 45-1/2024 (CPP-I/DU) dated 07.08.2024, had recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) SRFTI Society for fulfilment of certain conditions before declaration of Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), Kolkata, West Bengal as an Institution deemed to be University.

3. And further whereas, the Ministry of Education, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LOI) to the SRFTI Society for fulfilment of certain conditions within a period of 3 years before declaration of Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), Kolkata, West Bengal as an Institution deemed to be University.

4. And whereas, the SRFTI Society, vide letter dated 10.01.2025, submitted compliance report of the conditions of Letter of Intent (LoI). The compliance report was verified and accepted by the UGC Expert Committee. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 588th meeting (Item No.7.03) held on 25.03.2025.

5. Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), Eastern Metropolitan Bypass, Panchasayar, Kolkata, West Bengal as an Institution deemed to be University under distinct category. The said declaration is subject to the following conditions:

- i. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Central Government.
- ii. SRFTI, Kolkata shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- iii. The academic programmes to be offered at SRFTI, Kolkata shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.

- iv. SRFTI, Kolkata shall start new academic Courses/Programmes, Off-Campus(es), Off-Shore Campus(es) only in accordance with the norms and guidelines issued by the UGC, from time to time, on the subject.
- v. SRFTI, Kolkata shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes. The Institute shall not keep confined only to presently new emerging areas but it make endeavour to expand in other areas in accordance with the UGC Regulations / Guidelines as well as National Education Policy-2020.
- vi. SRFTI, Kolkata shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- vii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by SRFTI, Kolkata.
- viii. SRFTI, Kolkata shall submit its revised Memorandum of Association (MoA) / Rules to UGC/ Ministry of Education as per the provisions of the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 at the earliest. As and when necessary, the Institute shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- ix. SRFTI, Kolkata shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- x. SRFTI, Kolkata shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xi. SRFTI, Kolkata shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary